

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 13/24

GCMS NO 2024/25

1. नगेन्द्र व्यास पुत्र रघुनाथ प्रसाद जाति ब्राह्मण
2. मनोहर लाल पुत्र मुरारीलाल जाति महाजन (फौत)
3. शारदा देवी पत्नि विष्णुचंद जाति ब्राह्मण
4. विश्वास पुत्र विष्णुचंद जाति ब्राह्मण निवासीयान करौली तहसील व जिला करौली
5. रमेश चंद पुत्र सीताराम व्यास जाति ब्राह्मण (फौत)
- 6/1. मुन्नी देवी पत्नि स्व0रमेश चंद जाति ब्राह्मण
- 6/2. बालकृष्ण पुत्र स्व0रमेश चंद जाति ब्राह्मण
- 5/3. नगेन्द्र पुत्र स्व0रमेश चंद जाति ब्राह्मण निवासीयान भांकरी हाल शुक विहार कालोनी करौली तहसील व जिला करौली

अपीलांत

बनाम

1. रंगजी पुत्र देवपाल जाति मीना निवासी जोडली तहसील सपोटरा जिला करौली (हजफ)
2. तहसीलदार करौली
3. मुकुट बिहारी पुत्र मख्खनलाल जाति मीना निवासी जोडली तहसील सपोटरा जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरुद्ध मु0नं0 204/2008(120/1998) निर्णय व डिक्री दिनांक 18.1.24 न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली)

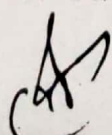
अभिभाषक अपीला0 श्री विष्णु चंद बंसल  
अभिभाषक रेस्पो0 श्री नेमी चंद गर्ग

दिनांक 16.7.2025

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 18.1.24 न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि अधिनस्थ न्यायालय में वादीगण/अपीलांतस ने एक वाद पत्र दफा 188-92 (ए) प 183 आर टी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी ख0न0 2812/11 रकबा 8 बीघा 9 विस्वा ग्राम कैलादेवी तहसील करौली वादीगण के शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त की स्थित है। प्रतिवादी न0 1 का आराजी मुतनाजा से किसी प्रकार का कोई ताल्लुक नहीं है प्रतिवादी न0 1 प्रभावशाली व्यक्ति है और सपोटरा विधानसभा से एम एल ए है और ताकत के बल पर जबरन जमीन में मदालखत कर काश्त करने पर उतारू हो रहा है। दिनांक 6.9.98 को जबरन आराजी में मदालखत कर संलग्न नक्शा वाद पत्र में बरंग सुर्य जिस्से में करीब 60 गुणा 100 फीट जमीन में नीव खोद कर उसे भरवाना शुरू कर दिया। वादीगण मना

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर

किया तो आमादा फिसाद हो गये और आगे भी निर्माण कार्य करने एवं पूरी जमीन पर कब्जा करने की धमकी दी है। इस प्रकार वादीगण प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का हकदार है -एवं जो निर्माण कार्य प्रतिवादीगण ने कराया है उससे प्रतिवादीगण को बेदखल कर निर्माण कार्य को प्रतिवादीगण के खर्चे पर हटवाया जावे तथा प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादीगण के खाते व कब्जे काश्त की विवादित आराजीयात पर किसी तरह से मद्दालखत मजाहमत नही करे ना ही किसी अन्य से करावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादीगण/अपीलांटस द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादीगण/अपीलांटस का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अभिभाषको की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यो, रिकार्ड व साक्ष्य के प्रतिकूल होने से एवं विधि विरुद्ध होने व खिलाफ कानून होने से निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय कतई आर्वेटेटरी परवर्स रेस्पो0 है। विधि के सुव्यवस्थित सिद्धान्तो के विपरीत पारित किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करते समय वादीगण अपीलांट की साक्ष्य पर भरोसा ना करने मे गंभीर त्रुटि की है निर्णय व डिक्री जैर अपील निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने रेस्पो0 की साक्ष्य पर भरोसा करने मे गंभीर त्रुटि की है। ऐसी स्थिति मे जैर अपील निर्णय निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात व साक्ष्य की सही प्रकार से विवेचना व विश्लेषण ना करने मे विधि की गंभीर त्रुटि की है। अधिनस्थ न्यायालय ने दावा पेशकर्ता के अभिवचनो के अनुसार तनकीयात कायम नही की है और बगैर तनकी बनाये ही अपीलांट/वादीगण का दावा विधि विरुद्ध रूप से खारिज किया गया है जो विधि के प्रावधानो के विपरीत है जो निरस्त किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 1 का फैसला विरुद्ध अपीलांट पारित करने मे विधिक भूल की है। तनकी न0 1 के तहत अपीलांट वादीगण को अपनी साक्ष्य से खसरा न0 2812/11 ग्राम कैलादेवी की खातेदारी व कब्जे काश्त की होना साबित करना था जिसके सर्मथन मे वादी ने जमाबंदी सम्वत 2052 से 2055 प्रदर्श 1 पेश की थी और मौखिक साक्ष्य पी डब्लू 1 अपीलांट वादी नगेन्द्र व्यास ने अपनी साक्ष्य मे उक्त आराजी पर अपना कब्जा काश्त होना कथन किया है। जिसके खण्डन मे रेस्पो0 प्रतिवादीगण द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य ख0न0 2812/11 के संबंध मे उनके द्वारा पेश नही की है। जिससे भूमि वादीगण अपीलांटस के खातेदारी की ना हो। अपीलांट ने विवाधक संख्या 1 को विधिवत तौर पर अपनी दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से साबित किया है जिसे अधिनस्थ न्यायालय ने भी अपीलांटस के पक्ष मे व प्रतिवादीगण के विरुद्ध तय कर निर्णित किया है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने जैर अपील निर्णय विधि विरुद्ध पारित करके दावा अपीलांटस खारिज करने मे भारी

राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर

भूल की है। ऐसी स्थिति में जैर अपील निर्णय विधि विरुद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है। तनकी संख्या 2 को भी अपीलांटस ने अपनी विधिवत साक्ष्य से साबित किया है कि वादग्रस्त आराजीयात ख0न0 2812/11 रकबा 5 बीघा 9 विस्वा ग्राम कैलादेवी प्रदर्श 1 जमाबंदी सम्वत 2052 से 2055 से वादीगण अपीलांट की खातेदारी व कब्जे काशत की होना साबित है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 2 का विवेचन विधि विरुद्ध रूप से करकर यह तनकी अपीलांटस के विरुद्ध व रेस्प0 के पक्ष में तय की है जबकि उक्त तनकी को साबित करने में सफल रहे हैं फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने वादीगण के हक में प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं करने में भारी कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में जैर अपील निर्णय निरस्त किये जाने योग्य है। तनकी संख्या 3 को भी अपीलांटगण ने अपनी विधिवत साक्ष्य से साबित किया है एवं मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रदर्श 2 व 3 से अपीलांटगण वादीगण ने उक्त आराजी में अनाधिकार निर्माण करना साबित किया है। खसरा न0 2812/11 वादीगण अपीलांटगण के खातेदारी व कब्जे की होना प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकृत तथ्य है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 3 का विवेचन गलत रूप से करकर यह तनकी विधि विरुद्ध रूप से अपीलांट वादीगण के विरुद्ध व प्रतिवादीगण रेस्प0 के पक्ष में तय करने में कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में जैर अपील निर्णय विधि विरुद्ध है जो निरस्त किये जाने योग्य है। तनकी संख्या 4 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण/रेस्प0 पर है। ख0न0 2812/11 ग्राम कैलादेवी की तरमीम ख0न0 2812/11 ग्राम कैलादेवी में होना कमिश्नर रिपोर्ट नायब तहसीलदार करौली प्रदर्श 2 व 3 से साबित है एवं ख0न0 2812/11 की तरमीम उप जिला कलेक्टर करौली के आदेश एवं तहसीलदार करौली के प्रस्ताव प्रदर्श 5 ता 7 से बखूबी साबित है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने ख0न0 2812/11 पर रेस्प0 प्रतिवादीगण के पक्ष में तय करने में भारी कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में जैर अपील निर्णय अधिनस्थ न्यायालय व तनकी संख्या 3 व 4 का विवेचन अपास्त किये जाने योग्य है। तनकी संख्या 5 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण रेस्प0 पर है इस संबंध में प्रतिवादीगण द्वारा दायरी दावा से पूर्व खसरा न0 2812/11 व 2812/12 का रूपान्तरण आबादी हुआ हो ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली में रेस्प0 प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके तहत अधिनस्थ न्यायालय ने इस विवादक को वादीगण के पक्ष में तय किया है फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट वादीगण के पक्ष में तय किया है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांटगण वादीगण का दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है। जो जैर अपील निरस्त किये जाने योग्य है। तनकी संख्या 6 को साबित करने का भार रेस्प0 प्रतिवादीगण पर था जिसके संबंध में उनके द्वारा कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रकरण में तरमीम की अपील राजस्व मंडल अजमेर में लंबित होने का पेश नहीं किया है जिसके खण्डन में अपीलांट/वादीगण द्वारा राजस्व मंडल के निर्णय दिनांक 12.2.21 की प्रमाणित प्रति प्रदर्श 4 पेश की है जिससे तरमीम की अपील खारिज हो चुकी है और दिनांक 1.2.93 को उप जिला कलेक्टर करौली द्वारा तरमीम अनुमोदन स्वीकार हुआ है। वह अंतिम है। फिर भी अधिनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 6 को अपीलांट/वादीगण के विरुद्ध व रेस्प0 के पक्ष में तय करने में कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में जैर अपील निर्णय अधिनस्थ न्यायालय निरस्त किये जाने योग्य है। तनकी संख्या 7 अनुतोष का विवेचन अधिनस्थ

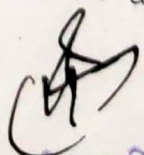


*(Handwritten signature)*

राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर

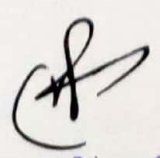
न्यायालय द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड व उपलब्ध साक्ष्य व तनकीयात के गलत विवेचन के आधार पर किया है। जो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व साक्ष्य के विपरीत है विधि विरुद्ध है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त वादीगण का दावा डिक्री नहीं कर खारिज कर कानूनी भूल की है। ऐसी स्थिति में जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलान्त की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री अपास्त किया जाकर दावा वादी/अपीलान्तगण डिक्री किया जावे।

रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री पूर्णतया विधि सम्मत व दस्तावेजों के अवलोकन के पश्चात ही पारित किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की गुजाईश नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष रेस्पोंडेंट द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर अंकित किया गया था कि खण्ड 2812/12 रामजीलाल उर्फ डिब्बा के नाम है किन्तु अपीलार्थी ने उक्त तथ्य की जानकारी होते हुए भी उस व्यक्ति को पक्षकार नहीं बनाया है। जबकि उपरोक्त वाद के निर्णय में उक्त व्यक्ति आवश्यक पक्षकार की हैसियत रखता है। इसलिए अपीलार्थी का वाद पक्षकारों के असंयोजन के कारण खारिज किये जाने योग्य है। सीपीसी के प्रावधान के तहत आदेश 1 नियम 9 के अनुसार कोई भी वाद पक्षकारों के असंयोजन के कारण विफल हो जावेगा यदि वह पक्षकार कोई वाद में आवश्यक पक्षकार की हैसियत रखता है, अपीलार्थीगण ने राजजीलाल उर्फ डिब्बा जो कि उपरोक्त वाद में आवश्यक पक्षकार की हैसियत रखता है को पक्षकार नहीं बनाया है इस कारण अपीलार्थीगण की अपील इस कानूनी बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रत्यर्थी संख्या 1 ता 3 ने लिखित बहस प्रस्तुत कर खसरा नं० 2812/12 में से प्रत्यर्थी संख्या 3 ने कुल 488.88 वर्गगज के दो भूखण्ड संख्या 1 व 2 के रूप में जरिये पंजीकृत दिनांक 13.10.97 को क्रय किये हैं तथा उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र प्रत्यर्थी संख्या 3 ने न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है जो प्रदर्श ए-2 है किन्तु उक्त विक्रय पत्र को निरस्त कराने का कोई अनुतोष अपीलार्थीगण ने अपने वाद से अधिनस्थ न्यायालय से नहीं चाहा है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि पंजीकृत विक्रय पत्र को सक्षम सिविल न्यायालय के द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है। अपीलार्थीगण ने न्यायालय के समक्ष यह स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि उसके द्वारा अन्य सिविल न्यायालय में कोई अन्य सिविल वाद विक्रय पत्र को निरस्त कराने के लिए प्रस्तुत किया है इसलिए उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र को निरस्त कराये वगैर अपीलार्थीगण का वाद मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का कानूनी रूप से पोषनीय नहीं है तथा इसी आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वाद खारिज किया गया है जो पूर्णतया विधि सम्मत आदेश है। उक्त विक्रय पत्र के पश्चात क्रय शुदा आराजी पर कब्जा प्रत्यर्थी संख्या 3 ने प्राप्त कर लिया है उस भूमि पर कब्जा वापस प्रदान करने का कोई अनुतोष नहीं चाहा है ना ही विक्रय पत्र पंजीकृत हो जाने के पश्चात स्वयं को प्रत्यर्थी संख्या 3 के द्वारा क्रयशुदा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने का कोई अनुतोष चाहा है इसलिए कब्जा वापिस के अनुतोष तथा घोषणा के अनुतोष के अभाव में अपीलार्थीगण की अपील कानूनी रूप से पोषनीय नहीं है। इसी आधार पर खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थीगण द्वारा केवल मात्र स्थाई

  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर

निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा जिस विवादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में वाद पेश किया गया है उस भूमि में से प्लॉट संख्या 1 व 2 अर्थात् 488.88 वर्गगज भूमि कृषि से आबादी भूमि में परिवर्तित हो चुकी है तथा उसके पट्टे की प्रत्यर्था संख्या 3 को जारी किये जो चुके हैं। जो प्रदर्श 4 है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि राजस्व न्यायालय को मात्र कृषि आराजीयात के संबंध में वाद सुनने का क्षेत्राधिकार है। आबादी भूमि के संबंध में वाद सुनने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है। बल्कि सिविल न्यायालय को प्राप्त है। इस प्रकार अपीलार्थीगण की अपील कानूनी रूप से पोषनीय नहीं होने से खारिज योग्य है। अपीलार्थीगण ने अपने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं किया कि वादग्रस्त कृषि भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा हो इसलिए वगैर कब्जे के अपीलार्थीगण की अपील खारिज किये जाने योग्य है। कानून में स्पष्ट प्रावधान है कि किसी सम्पत्ति के वास्तविक स्वामी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्रदान नहीं किया जा सकता है। इसलिए अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से निर्णय पारित किया है। अपीलार्थीगण ने अपने अभिवचनो, मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य से ख0न0 2812/11 का स्वयं को स्वामी साबित नहीं किया है तथा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज मात्र फिस्कल एन्ट्री होती है तथा वह प्रविष्टि किसी भी कृषि आराजीयात के स्वामित्व का सबूत नहीं होती है। अपीलार्थीगण द्वारा केवल मात्र जमाबंदी के अलावा अन्य कोई दस्तावेज साक्ष्य वादग्रस्त भूमि के स्वामित्व के संबंध में प्रस्तुत नहीं किये हैं। अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा अपने वाद को साबित नहीं करने के कारण ही अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिक रूप से वाद पत्र खारिज किया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर वादी एवं प्रतिवादीगण की साक्ष्य ली जाकर प्रत्येक तनकी का विवेचन किये जाने के उपरान्त ही निर्णय व डिकी पारित की गई है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विवादित भूमि पर खरीद के समय से ही कब्जा रेस्पो0 का माना है। इस प्रकार अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील आर्बीट्रेरी परवर्स व केप्रिसियस है। इस प्रकार अपीलार्थीगण की अपील खारिज योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा अपीलार्थीगण निर्णय एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद पत्र में यह तथ्य अंकित किया गया था कि आराजी ख0न0 2812/11 रकबा 8 बीघा 9 विस्वा ग्राम कैलादेवी तहसील करौली वादीगण की शामिलती कब्जे काश्त की खातेदारी की भूमि है। जिस पर प्रतिवादी न0 1 द्वारा बिना किसी अधिकार के रकबा 60 गुणा 100 अर्थात् 488.88 वर्ग गज भूमि पर जबरन नीब खोदकर निर्माण कार्य किये जाने के कारण रेस्पो/प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने एवं विवादित आराजीयात से प्रतिवादीगण को बेदखल किये जाने की प्रार्थना अधिनस्थ न्यायालय से की गई थी। पत्रावली में उपलब्ध बयनामा दिनांक 13.10.97 के अनुसार आराजी ख0न0 2812/12 के खातेदार बाबूलाल पुत्र रामजीलाल जाति कायस्थ निवासी कैलादेवी से प्रतिवादी मुकुट बिहारी पुत्र मखन लाल जाति मीना निवासी जोडली तहसील सपोटरा ने जरिये बयनामा 488.88 वर्गगज भूमि कय की गई है। उक्त कय शुदा भूमि का आबादी

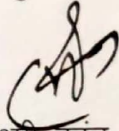
  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर

मे संपरिवर्तन तहसीलदार करौली के आदेश दिनांक 18.12.97 के द्वारा किया जा चुका है। प्रतिवादी द्वारा कय की गई भूमि के खातेदार रामजीलाल उर्फ डिब्बा को अपीलांट द्वारा ना तो दावे मे पक्षकार बनाया गया है ना ही अपील मे पक्षकार बनाया है। जो हस्तगत प्रकरण मे उचित पक्षकार की हैसियत रखता है। इस प्रकार अपीलांट की अपील पक्षकारो के असंयोजन से भी बाधित है। अपीलांट द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है जिससे की आराजी ख0न0 2812/11 मे रेसपो/प्रतिवादी द्वारा निर्माण कार्य किया जा रहा हो। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से प्रकरण मे तनकीयात कायम की जाकर प्रत्येक तनकी पर वादी एवं प्रतिवादी की साक्ष्य ली जाकर तनकीवार विवेचन किये जाने के उपरान्त ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जिसमे किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से, उसमे किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट खारिज योग्य होने से खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर करौली के मु0नं0 204/08 (120/1998) मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.01.2024 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 16.7.2025 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।



  
(लक्ष्मी कांत बालोत)  
राजस्व अपील प्राधिकारी  
सवाई माधोपुर